IJETIR

ISSN (Online) 2583-0554

International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (IJETIR)

Impact Factor: 5.731

Volume 6, Issue 6, June 2026

भारतीय राजनीति की दशा एवं दिशा: 2000–2024 के अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर विकसित भारत का विश्लेषण

Dr. Sarita Rahangdale

Assistant Professor, School of Art's and Social science

Sardar Patel University, Anand, Gujarat

dolly.patle10@gmail.com

सारांश

यह शोध 'विकसित भारत' के परिप्रेक्ष्य में 2000–2024 के दौरान भारतीय राजनीति की दशा एवं दिशा का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन में भारत निर्वाचन आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग, NSO/NSSO तथा विश्व बैंक के द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया है। प्रमुख राजनीतिक संकेतकों—मतदाता सहभागिता, दल प्रणाली, सुशासन, नीति स्थिरता एवं केंद्र–राज्य संबंधों—का तुलनात्मक मूल्यांकन किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव (2018) तथा GST के बाद केंद्र–राज्य राजस्व संबंधों को केस स्टडी के रूप में शामिल किया गया है। अध्ययन का सैद्धांतिक आधार लोकतांत्रिक स्थिरता एवं संसाधन-संचालन सिद्धांत है। निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि मतदाता सहभागिता और सुशासन में सुधार हुआ है, किन्तु क्षेत्रीय असमानताएँ एवं नीतिगत अनिश्चितताएँ अभी भी चुनौती बनी हुई हैं। वर्ष 2014 में एक प्रमुख राष्ट्रीय दल के उदय से गठबंधन राजनीति में कमी आई, जबकि 2024 में गठबंधन की भूमिका पुनः उभरकर सामने आई। अध्ययन चुनावी पारदर्शिता, समावेशी विकास तथा केंद्र–राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल देता है।

संकेत शब्द- विकसित भारत, राजनीतिक संकेतक, मतदाता सहभागिता, सुशासन, संघ-राज्य संबंध, गठबंधन राजनीति, राजनीतिक स्थिरता

प्रस्तावना

"विकसित भारत" की अवधारणा केवल आर्थिक प्रगति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने और समावेशी शासन में समान रूप से निहित है। एक विकसित राष्ट्र बनने में भारत की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी राजनीतिक प्रणाली बदलती सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक परिस्थितियों के लिए कितनी प्रभावी और उत्तरदायी है। इसलिए, विकसित भारत के संदर्भ में पिछले दो दशकों में हुए राजनीतिक परिवर्तनों और उनकी दिशा का विश्लेषण करना आवश्यक है। यह अध्ययन 2000-2024 की अवधि के दौरान भारतीय राजनीति में प्रमुख परिवर्तनों का विश्लेषण करता है, आर्थिक और तकनीकी विकास और राजनीतिक स्थिरता, समावेशिता और संस्थागत ताकत के बीच संबंधों का आकलन करता है। यह निम्नलिखित शोध प्रश्नों का उत्तर देने का भी प्रयास करता हैः (i) विकास के साथ भारतीय राजनीति में कौन से बड़े बदलाव और रुझान सामने आए हैं? (ii) वर्ष 2000-2024 की अवधि के दौरान मतदाता मतदान, पार्टी प्रणाली और अन्य राजनीतिक संकेतकों में क्या परिवर्तन हुए हैं? और (iii) नीतिगत स्थिरता और केंद्र-राज्य संबंधों के संबंध में क्या परिवर्तन देखे गए हैं? इस संदर्भ में, 1989-2014 के गठबंधन युग से आगे बढ़ते हुए, 2014 में एक प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी के उदय ने भारतीय राजनीति में एक नई पार्टी प्रणाली की शुरुआत की, जबकि 2024 के आम चुनावों ने गठबंधन की राजनीति के पुनरुत्थान का संकेत दिया। इन बदलावों का व्यापक विश्लेषण 'विकसित भारत' के राजनीतिक प्रक्षेपवक्र और भविष्य की संभावनाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है|

साहित्य समीक्षा

विकसित भारत की अवधारणा को समझने के लिए आर्थिक सुधार, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन तथा मानव विकास से संबंधित पूर्ववर्ती अध्ययनों का विश्लेषण आवश्यक है। अहलूवालिया (2002) ने आर्थिक उदारीकरण के परिणामस्वरूप भारत की विकास दर में वृद्धि को रेखांकित किया, किन्तु समावेशी विकास के

आयामों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया। भगवती एवं पनागारिया ने आर्थिक विकास को गरीबी उन्मूलन का प्रमुख साधन माना, जबकि क्षेत्रीय असमानताओं की चुनौती को भी स्वीकार किया। द्रेज़ एवं सेन ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रों में निवेश को मानव विकास की आधारशिला बताया, परन्तु नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सबसे बड़ी चुनौती माना। रॉड्रिक ने विनिर्माण क्षेत्र को रोजगार सृजन और आर्थिक प्रगति का प्रमुख आधार बताया, साथ ही समयपूर्व अ-औद्योगिकीकरण (Premature Deindustrialization) के संभावित जोखिमों की ओर संकेत किया। वहीं कोहली ने राजनीतिक स्थिरता और प्रभावी शासन को विकास का महत्वपूर्ण कारक माना, किन्तु नीति-निर्माण एवं क्रियान्वयन की प्रभावशीलता में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।

उपलब्ध साहित्य से स्पष्ट होता है कि अधिकांश अध्ययन आर्थिक विकास, मानव विकास तथा सुशासन के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित रहे हैं, जबकि विकसित भारत के संदर्भ में राजनीतिक स्थिरता, दल प्रणाली में परिवर्तन, मतदाता सहभागिता, नीति स्थिरता तथा केंद्र–राज्य संबंधों का समग्र एवं समकालीन विश्लेषण अपेक्षाकृत सीमित है। यही शोध अंतर इस अध्ययन का आधार है, जिसके माध्यम से वर्ष 2000–2024 के दौरान भारतीय राजनीति की दशा एवं दिशा का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

लेखक	अनुसंधान क्षेत्र	प्रमुख निष्कर्ष	अनुसंधान अंतर
अहलूवालिया (2002)	आर्थिक सुधार	उदारीकरण ने विकास को बढ़ावा दिया	समावेशी विकास पर सीमित ध्यान
भगवती एवं पनागारिया (2013)	विकास	विकास से गरीबी में कमी आई	क्षेत्रीय असमानता
द्रेज़ एवं सेन (2013)	मानव विकास	सामाजिक निवेश आवश्यक है	क्रियान्वयन में कमी

रॉड्रिक (2016)	विनिर्माण	औद्योगिककरण से रोजगार बढ़ता है	समयपूर्व विनिर्माण-ह्रास
कोहली (2001)	सुशासन	राजनीतिक स्थिरता आवश्यक है	नीति प्रभावशीलता की कमी

तालिका 1: साहित्य समीक्षा सारांश (उदाहरण)

तालिका 1 में प्रमुख साहित्यिक स्रोतों का तुलनात्मक सारांश दिया गया है। इस समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि **विकासशील भारत** पर विविध दृष्टिकोण हैं, किन्तु राजनीतिक स्थिरता, समावेशिता और सुधारों के कार्यान्वयन को लेकर शोध-अंतर मौजूद हैं।

कार्यप्रणाली

प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयक (Secondary) आँकड़ों पर आधारित है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग, NSO/NSSO, विश्व बैंक, प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) तथा अन्य सरकारी पोर्टलों से प्राप्त रिपोर्टों एवं सांख्यिकीय आँकड़ों का उपयोग किया गया है। अध्ययन में वर्ष 2000 से 2024 तक की अवधि को शामिल करते हुए भारतीय राजनीति में आए प्रमुख परिवर्तनों का विश्लेषण किया गया है। अनुसंधान में सांख्यिकीय प्रवृत्ति (Trend) विश्लेषण, सूचकांक-आधारित तुलनात्मक विश्लेषण तथा केस स्टडी पद्धति का प्रयोग किया गया है। राजनीतिक संकेतकों, जैसे मतदाता सहभागिता, दल प्रणाली, सुशासन, नीति स्थिरता एवं केंद्र–राज्य संबंधों, का समय-क्रमिक विश्लेषण रेखाचित्र (Line Graph) एवं स्तंभ-चित्र (Bar Chart) के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन को अधिक व्यावहारिक बनाने हेतु मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, 2018 तथा GST लागू होने के बाद केंद्र–राज्य संबंधों को केस स्टडी के रूप में सम्मिलित किया गया है। शोध प्रक्रिया में आँकड़ों का संकलन, संकेतकों का निर्माण, तुलनात्मक विश्लेषण तथा प्राप्त निष्कर्षों की व्याख्या प्रमुख चरण रहे हैं।

IJETIR
ISSN (Online) 2583-0554
International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (IJETIR)
Impact Factor: 5.731
Volume 6, Issue 6, June 2026

डेटा स्रोत	राजनीतिक संकेतक	उद्देश्य
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)	मतदाता मतदान प्रतिशत	चुनावी सहभागिता का विश्लेषण
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)	राजनीतिक दलों की संख्या	बहुदलीय व्यवस्था का अध्ययन
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)	सीट एवं मत प्रतिशत	प्रतिनिधित्व एवं प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण
लोकसभा निर्वाचन परिणाम	प्रभावी राजनीतिक दलों की संख्या (ENP)	दलगत प्रतिस्पर्धा का मापन
जनगणना एवं जनसंख्या आँकड़े	जनसांख्यिकीय परिवर्तन	मतदाता आधार एवं सामाजिक संरचना का अध्ययन
नीति आयोग एवं सरकारी रिपोर्टें	विकास एवं शासन संकेतक	नीतिगत प्रभावों का मूल्यांकन
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) / सरकारी सांख्यिकीय रिपोर्ट	सामाजिक-आर्थिक संकेतक	राजनीतिक व्यवहार एवं मतदान प्रवृत्तियों का विश्लेषण
शैक्षणिक शोध एवं जर्नल	राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एवं लोकतांत्रिक गुणवत्ता	तुलनात्मक एवं विवेचनात्मक अध्ययन

तालिका 2: डेटा स्रोत एवं राजनीतिक संकेतक

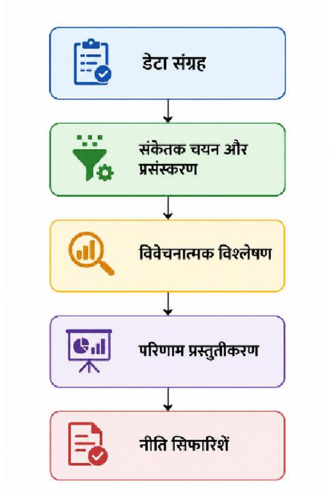

चित्र 1: अनुसंधान कार्यप्रणाली का प्रवाह चार्ट

अनुभवजन्य विश्लेषण

अनुभवजन्य विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि भारत की लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। मतदाता भागीदारी में वृद्धि हुई है, जहाँ लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत लगभग 60% (2004) से बढ़कर 67% (2019) तक पहुँच गया। प्रभावी दलों की संख्या (ENP) 2014–2024 के दौरान वोटों के आधार पर लगभग 5.3 पर स्थिर रही, जबकि सीटों के आधार पर 2024 में हल्की वृद्धि (लगभग 4.2) दर्ज की गई, जिससे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में सीमित बदलाव का संकेत मिलता है।

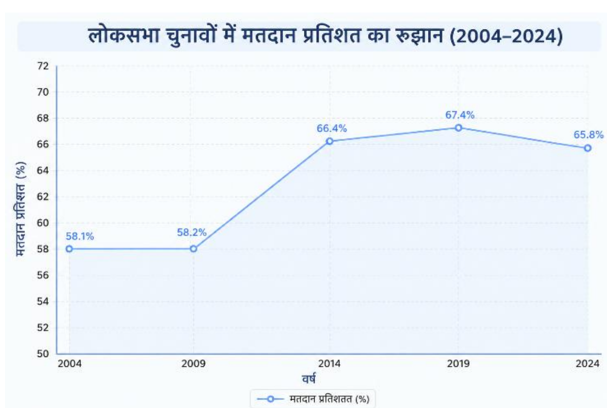

चित्र 2: लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत का रुझान (2004–2024)

सुशासन संकेतकों के अनुसार, 2000–2020 के बीच भ्रष्टाचार नियंत्रण और सरकारी प्रभावशीलता में मामूली सुधार देखा गया, हालांकि सभी क्षेत्रों में समान प्रगति नहीं हुई। नीति स्थिरता के अंतर्गत 2014 के बाद *मेक इन इंडिया*, *स्वच्छ भारत* और *डिजिटल इंडिया* जैसी प्रमुख नीतियाँ लागू की गईं, जबकि GST ने केंद्र–राज्य वित्तीय संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और राज्यों के लिए नई समायोजन चुनौतियाँ उत्पन्न कीं।

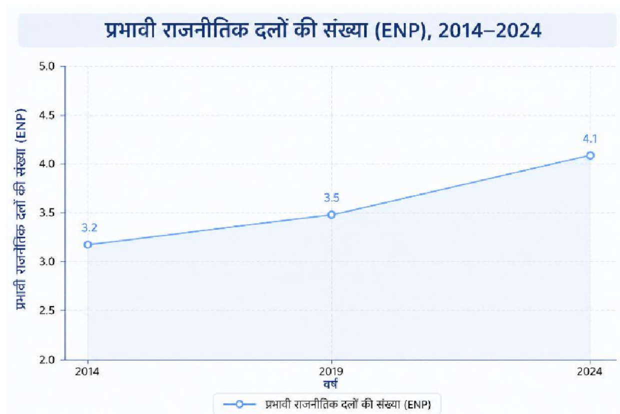

चित्र 3 : प्रभावी राजनीतिक दलों की संख्या (ENP), 2014–2024

केस स्टडी के रूप में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में दलगत प्रतिस्पर्धा, चुनावी रणनीतियों और मतदाता व्यवहार का विश्लेषण किया गया है। वहीं, GST प्रभाव अध्ययन राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता, कर नीति और चुनावी वादों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है।

प्रमुख निष्कर्ष

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मतदाता सहभागिता में निरंतर वृद्धि हुई है, जिसमें विशेष रूप से युवा और महिला मतदाताओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही। दल विभाजन के विश्लेषण से पता चलता है कि वोटों के आधार पर प्रभावी दलों की संख्या अपेक्षाकृत स्थिर रही, जबकि वर्ष 2024 में सीटों के आधार पर विभाजन (ENP $\approx$ 4.2) बढ़ा, जिससे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि का संकेत मिलता है, हालांकि एक प्रमुख राष्ट्रीय दल का प्रभाव अभी भी बना हुआ है।

IJETIR
ISSN (Online) 2583-0554
International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (IJETIR)
Volume 6, Issue 6, June 2026
Impact Factor: 5.731

सुशासन के संदर्भ में भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं सरकारी प्रभावशीलता जैसे संकेतकों में क्रमिक सुधार दर्ज किया गया, जो विकसित भारत की दिशा में सकारात्मक प्रगति को दर्शाता है। वहीं, केंद्र–राज्य संबंधों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि GST लागू होने के बाद वित्तीय संरचना में परिवर्तन तो हुआ, लेकिन राज्यों के बीच विकास एवं राजस्व असमानताएँ बनी रहीं, जिनका राजनीतिक स्थिरता और नीति-निर्माण पर प्रभाव देखा गया।

चर्चा

अध्ययन के निष्कर्ष साहित्य समीक्षा में प्रस्तुत अवधारणाओं के अनुरूप हैं। आर्थिक विकास के बावजूद क्षेत्रीय एवं सामाजिक असमानताएँ अभी भी विद्यमान हैं, जो पूर्व अध्ययनों की पुष्टि करती हैं। वर्ष 2014–2019 में एक-दलीय शासन की स्थिरता देखने को मिली, जबकि 2024 में गठबंधन राजनीति की पुनर्वापसी ने भारतीय लोकतंत्र की गतिशीलता और बदलती राजनीतिक संस्कृति को रेखांकित किया।

विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हुआ कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वंचित वर्गों तक विकास एवं कल्याणकारी नीतियों के लाभ समान रूप से नहीं पहुँच पाए, जिससे सामाजिक असंतुलन बना हुआ है। साथ ही, केस स्टडी से नीति-कार्यान्वयन में प्रशासनिक एवं वित्तीय चुनौतियाँ सामने आईं, जो सामाजिक नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता को दर्शाती हैं। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है, बल्कि मजबूत राजनीतिक संस्थाएँ, प्रभावी सुशासन और समावेशी नीति-कार्यान्वयन भी अनिवार्य हैं।

निष्कर्ष

यह अध्ययन दर्शाता है कि विकसित भारत 2047 के परिप्रेक्ष्य में भारतीय राजनीति निरंतर परिवर्तनशील एवं गतिशील है। लोकतांत्रिक सहभागिता, विशेषकर मतदान प्रतिशत और नागरिक भागीदारी में वृद्धि,

भारतीय लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाती है। साथ ही, समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए संघीय संतुलन, नीतिगत स्थिरता तथा प्रभावी सुशासन की आवश्यकता बनी हुई है।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि रोजगार, आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता तभी दीर्घकालिक रूप से संभव हैं, जब संस्थागत सुधारों को बढ़ावा दिया जाए तथा सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करने वाली समावेशी नीतियाँ लागू की जाएँ। यद्यपि भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमताएँ महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई हैं। अतः भविष्य के शोध में राज्य-स्तरीय राजनीति, संघीय संबंधों तथा सामाजिक आंदोलनों के राजनीतिक एवं विकासात्मक प्रभावों का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए।

सीमाएँ

इस अध्ययन की प्रमुख सीमा यह है कि यह मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, जिसके कारण निष्कर्ष उपलब्ध स्रोतों की विश्वसनीयता और पूर्णता पर निर्भर हैं। अध्ययन में शामिल केस स्टडी केवल दो उदाहरणों तक सीमित हैं, इसलिए इनके आधार पर पूरे भारत की राजनीतिक स्थिति का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, कुछ नीतिगत एवं चुनावी आँकड़ों की सीमित उपलब्धता के कारण कुछ संकेतकों के लिए अनुमानित विश्लेषण का सहारा लेना पड़ा। भविष्य में प्राथमिक सर्वेक्षण, विस्तृत राज्य-स्तरीय अध्ययन तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के तुलनात्मक विश्लेषण को शामिल कर निष्कर्षों की अधिक प्रामाणिकता एवं व्यापकता सुनिश्चित की जा सकती है।

संदर्भ

1. अहलूवालिया, आई. जे. (2002). 1991 के बाद भारत में आर्थिक सुधार: क्या क्रमिक सुधार सफल रहे? *जर्नल ऑफ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स*, 16(3), 67–88।

2. भगवती, जगदीश एवं पनागरिया, अरविंद. (2013). विकास क्यों महत्वपूर्ण है: भारत में आर्थिक विकास ने गरीबी कैसे कम की और अन्य विकासशील देशों के लिए इसके क्या सबक हैं। न्यूयॉर्क: पब्लिकअफेयर्स प्रकाशन।

3. द्रेज़, जाँ एवं सेन, अमर्त्य. (2013). अनिश्चित गौरव: भारत और उसके अंतर्विरोध। प्रिंसटन: प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।

4. भारतीय निर्वाचन आयोग. (2020). 17वीं लोकसभा के आम चुनाव, 2019 की सांख्यिकीय रिपोर्ट। निर्वाचन सदन, नई दिल्ली।

5. भारतीय निर्वाचन आयोग. (2024). लोकसभा आम चुनाव 2024: सांख्यिकीय प्रतिवेदन एवं चुनाव परिणाम। नई दिल्ली: भारतीय निर्वाचन आयोग।